

Newspaper Clips November 26-28, 2016

November 28

Hindustan ND 28.11.2016 P-5

आईआईटी में 400 सीटें बढ़ेंगी



नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

आईआईटी दिल्ली में अगले वर्ष से डिजाइन विभाग शुरू होने जा रहा है। इससे यहां बॉटेक और एमटेक में 400 के करीब सीटों की बढ़ोतरी होगी।

आईआईटी दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि अभी सिर्फ आईआईटी गुवाहटी में ही डिजाइन विभाग है, जबकि अन्य आईआईटी डिजाइनिंग के कुछ प्रोग्रामों का ही संचालन करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली ने अगले वर्ष से डिजाइन विभाग शुरू करने का निर्णय लिया है।

डिजाइन विभाग में शुरू होने वाले कोर्स में तकनीक के साथ सौन्दर्यशास्त्र का भी समावेश किया जाएगा। पाठ्यक्रम की सामग्री और योजना अभी तैयार हो रही है। इस विभाग के अंतर्गत शुरू होने वाले पाठ्यक्रम में विज्ञान के अलावा अन्य पृष्ठभूमि के छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस विभाग में एडमिशन के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।



फाइल फोटो

विदेशी अध्यापकों को लाने पर जोर

आईआईटी दिल्ली अभी दुनिया के 100 संस्थानों की रैंकिंग में शामिल नहीं है। अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए आईआईटी दिल्ली के प्रशासन ने विदेशी शिक्षकों को नौकरी पर रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के साथ आईआईटी दिल्ली का एक प्रतिनिधिमंडल जनवरी माह में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का दौरा करेगा। वहां इसकी संभावनाओं को तलाश जाएगा, ताकि यहां पर विदेशी शिक्षकों को नियुक्त किया जा सके।

बिना छात्रावास सुविधा पीएचडी-पीजी में प्रवेश

पीएचडी और स्नातकोत्तर (पीजी) के कुछ छात्रों को अगले वर्ष से कैंपस में छात्रावास की सुविधा नहीं मिलेगी। आईआईटी दिल्ली के पास जगह की बहुत कमी है और छात्रावास बहुत सीमित है। आईआईटी में यदि हर छात्र को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी तो सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। इस वजह से आईआईटी ने तय किया है कि वह पीएचडी और पीजी के 20 से 25 प्रतिशत छात्रों को अगले वर्ष से आवास सुविधा नहीं देगा।

100 टॉप संस्थानों की सूची में शामिल होने के लिए प्रयास जारी

25 फीसदी विद्यार्थियों को अगले साल से छात्रावास नहीं मिलेगा

पीएचडी की सीटें 500 से अधिक की जाएंगी

आईआईटी दिल्ली पीएचडी की सीटों में प्रति वर्ष 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी करेगा और अगले पांच साल में इनकी संख्या 500 से अधिक करने की योजना है। शिक्षाविदों के अनुसार, नए आईआईटी को अच्छे शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए देश में पीएचडी की सीटों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है और यह काम पुराने आईआईटी को ही करना होगा।

गुणवत्ता पर असर नहीं

आईआईटी के एक अधिकारी के अनुसार, पीएचडी की सीटें बढ़ाने पर ऐसा नहीं है कि हमारी गुणवत्ता पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल आईआईटी दिल्ली में पीएचडी की सीटें 250 के आसपास हैं।

Nav Bharat Times ND 28.11.2016 P-4

CBSE बनाएगा आधार कार्ड

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईईई) के लिए अब तक जिन स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, उनकी मदद सीबीएसई करेगा। सीबीएसई ने हर उस शहर में आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट वास्ते 104 फैंसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, जहां एग्जामिनेशन होगा। इन सेंटर्स में स्टूडेंट्स जाकर बिना किसी फीस के आधार कार्ड के लिए एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट www.jee-main.nic.in में इन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। जिन्होंने आधार के लिए एनरोल कर लिया है, मगर

एग्जाम वाले शहरों में खोले गए हैं 104 सेंटर्स

फॉर्म भरने तक उन्हें कार्ड नहीं मिलता है, तो वे जेईईई मेन 2017 के ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फॉर्म में 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी भर सकते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले ऑनलाइन ऐप्लिकेशन प्रोसेस के लिए स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड बनवाने शुरू कर दिए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर के लिए ऐप्लिकेशन दे सकते हैं, जिसके लिए वे www.uidai.gov.in पर दी गई सेंटर लिस्ट में से कहीं भी जा सकते हैं। सीबीएसई ने भी हर उस शहर में अपने फैंसिलिटेशन सेंटर शुरू कर दिए हैं, जहां एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। बोर्ड

का कहना है, इन सेंटर्स में स्टूडेंट्स जाकर बिना किसी फीस के आधार कार्ड के लिए एनरोल कर सकते हैं। जिसने आधार के लिए एनरोल कर लिया है, मगर फॉर्म भरने तक उन्हें आधार कार्ड नहीं मिलता है, तो वे जेईईई मेन 2017 के ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फॉर्म में 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी भर सकता है। यह वो आईडी है, जो आधार एनरोलमेंट स्लिप में मौजूद होती है।

बोर्ड का कहना है कि अगर फैंसिलिटेशन सेंटर्स पर आधार एनरोलमेंट फैंसिलिटिटी नहीं मिलती है, तो कैंडिडेट आधार एनरोलमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट भरे। सेंटर उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, जो उन्हें ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फॉर्म भरते वक्त एंटर करना होगा।

Virat Vaibhav ND 28.11.2016 P-7

आवेदकों के आधार कार्ड से होगा डाटा का मिलान

नई दिल्ली (ब्यूरो)। जेईई-मेन की परीक्षा में आवेदकों के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य करने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा है कि अब आवेदकों के आधार डाटा का मिलान भी किया जाएगा। अगर छात्र द्वारा दी गई जानकारी आधार में उपलब्ध जानकारी के साथ मेल नहीं खाती है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सीबीएसई ने छात्रों को सलाह दी है कि वे फॉर्म भरने से पहले सभी सूचनाओं को जांच लें। सीबीएसई के मुताबिक आधार कार्ड वाला आवेदक ही जेईई-मेन में आवेदन कर पाएगा। किसी को दिक्कत न हो इसलिए सीबीएसई अब खुद छात्रों को आधार कार्ड बनवाने में मदद करेगी। अब सीबीएसई ने निर्देश

जेईई मेन : सीबीएसई ने जारी किया आदेश स्कूल की जन्मतिथि व आधार की जन्मतिथि मिलाई जाएगी

दिया है कि जेईई-मेन के आवेदकों का डाटा आधार कार्ड में दिए गए डाटा से मिलान होगा। जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इसमें छात्रों की जन्म तिथि, जेंडर समेत अन्य जानकारी शामिल होगी। अगर किसी छात्र ने हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अलग जन्मतिथि और आधार कार्ड में अलग जानकारी दी होगी। तो मिलान के बाद उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जेईई मेन के लिए एक दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहा है।

Virat Vaibhav ND 28.11.2016 P-8

जल प्रबंधन पर विशेषज्ञों के

गहन मंथन की जरूरत: गहलौत

एजेंसी ■ हरिद्वार

आईआईटी रुड़की में जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित खाद्य सुरक्षा के लिए सिंचाई प्रबंधन में चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ केंद्रीय मंत्री टीसी गहलौत ने किया। दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश का वायुमंडल बेहतर है। यहां गंगा बहती है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। कहा कि जरूरत से अधिक खाद और पानी फसलों को देने से उनके खराब होने

का खतरा रहता है। जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों को गहन मंथन करना चाहिए। क्योंकि, किसी राज्य में अधिक सुख तो कहीं बाद जैसी समस्या है। सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जल ही जीवन है। उन्होंने कहा कि इसके संस्करण और संवर्धन की जरूरत है। इस मौके पर एनआइएच के निदेशक आरडी सिंह, प्रोफेसर यूपी सिंह, डा. एसके मिश्रा, एम गोपालकृष्णन आदि मौजूद रहे।

Mint ND 28.11.2016 P-20

Govt disaster relief body to be studied as a business model

BY SHASWATI DAS

shaswati.d@livemint.com

NEW DELHI

What is being seen as the ministry of home affairs' (MHA) attempt at upping its brand value, its disaster response arm—the National Disaster Response Force (NDRF)—is now the subject of a case study involving an organization working in a high-risk area.

The case study by the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi is projecting NDRF as a public sector brand to explore change, leadership and branding initiatives in large-scale organizations.

The study is set to be launched in the Indian Institutes of Management (IIMs), where business management students will be taught "appropriate brand management strategies that lead to the success of an organization which is not working for profit".

According to government statistics, every year nearly 4.8 million people are affected by natural and man-made disasters in India—a number that is likely to go up to nearly 19 million by 2030.

"This will be a huge boost for the organization, which is at the forefront of managing a disaster. The most important exercise that we had undertaken was when the Nepal earthquake struck in 2015, which killed more than 9,000 people and left more than 22,000 injured. The NDRF had sent out 16 teams that conducted night rescue operations to pull out people from the debris," said O.P. Singh,

director general of the Central Industrial Security Force and former director general of NDRF.

All was not well with the NDRF till a year ago, when the organization's resources and operations languished under neglect. In March 2015, the standing committee on the MHA noted that the budget allotment to NDRF in 2014-15—Rs200 crore—had been returned unspent. The budget estimates were later revised to Rs50 crore, but only a little more than Rs7 crore of this amount was spent.

"There was no focus or interest to develop the force in the last 10 years. Nobody was interested in making it work or buying equipment that we desperately needed. It was just another ordinary organization," Singh added.

A step in the right direction was taken late last year, when the NDRF spent Rs52 crore to buy equipment such as gas and hydraulic cutters.

Although the NDRF was set up as a mandated response force under the Disaster Management Act, 2005, MHA officials said the onus of responding to disasters was on the states.

"The NDRF is still growing. No organization is up and running overnight. It has made huge progress and is one of the most effective response teams in India. In case of any natural disaster, it is the state that needs to act first and the NDRF supplements those relief efforts," said an MHA official requesting anonymity.

The number of NDRF battalions has grown from six in 2006 to 12 now.

November 27

Business Standard ND 27.11.2016 P-12

IIT-Kharagpur among top 100 in new employability rankings

VINAY UMARI
Ahmedabad, 26 November

Quacquarelli Symonds (QS) has released the first edition of a new ranking on graduate employability that has seen IIT-Kharagpur (IIT-KGP) emerge as the only Indian institute in the top 100. Other institutes such as IIT-Madras, IIT-Delhi and IIT-Bombay have been ranked in the 101-150 bands in the QS Graduate Employability Rankings 2017, followed by IIT-Kanpur and University of Delhi in the over 201 band.

The new ranking, which features 300 top universities globally, is designed to improve the quality of analyses about the links between university practices and graduate employability.

Globally, the first edition of QS Graduate Employability Rankings 2017 has seen Stanford University and Massachusetts Institute of Technology (MIT) bag first and second places, respectively, followed by China's Tsinghua University in third place.

According to QS, universities with a strong STEM focus, particularly those emphasising on technology, have been ranked higher.

The methodology for the QS Graduate Employability Rankings differs from that found in the global rankings, using different indicators and changing the weighting of the existing indicators

The new ranking, which features 300 top universities globally, is designed to improve the quality of analyses about the links between university practices and graduate employability



that it retains.

The rankings' first edition is based on five criteria, including employer reputation with a weightage of 30 per cent, partnerships with employers (25 per cent), alumni outcomes (20 per cent), employers' presence on campus (15 per cent) and graduate employment rate

(10 per cent).

Among the criteria, IIT-Madras scored 96.6/100 for graduate employment rate, making it India's highest-scoring university for this indicator, and the fourth-highest scoring university in the world for this metric. On the other hand, University of Delhi scored 98.6/100 for alumni outcomes, thereby being ranked at 13th position globally for this indicator.

Commenting on the rankings, Ben Sower, head of research at QS said, "As the global employment market changes in unprecedented ways, stu-

dents are increasingly emphasising the link between their university choice and their future career. We are confident that the insights provided by this ranking will prove invaluable in allowing them to do so."

The ranking represents a development on last year's pilot, with an enhanced methodology and an additional 100 universities ranked.

Globally, the top 20 comprises institutions from the United States (10), the United Kingdom and China (three each), Australia (2), France (1), and Hong Kong (1).

HIRING ODDS

QS Graduate Employability Ranking 2017: **INDIA**

Rank	Institution
81-90	Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)
101-150	Indian Institute of Technology Madras (IIT-M)
101-150	Indian Institute of Technology Bombay (IIT-B)
101-150	Indian Institute of Technology Delhi (IIT-D)
201+	University of Delhi
201+	Indian Institute of Technology Kanpur (IIT-K)

QS Graduate Employability Rankings 2017: **TOP 10**

Rank	Institution	Country
1	Stanford University	United States
2	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	United States
3	Tsinghua University	China
4	The University of Sydney	Australia
5	University of Cambridge	United Kingdom
6	Ecole Polytechnique ParisTech	France
7	Columbia University	United States
8	University of Oxford	United Kingdom
9	University of California, Berkeley (UCB)	United States
10	Princeton University	United States

Times Of India ND 27.11.2016 P-7

More PSUs line up at IITs for placements

Somdatta.Basu
@timesgroup.com

Kolkata: The number of public sector undertakings (PSUs) lining up to take part in IIT placements has seen a sharp rise this year. Almost all major IITs have more than double the number of PSUs — both Maharatnas and Navratnas — queuing up to participate in the recruitment process that begins on December 1. Isro, DRDO and Navy will also join the process.

At IIT-Kharagpur, the country's oldest IIT, the number of PSUs confirming partici-

Bigger PSU participation will change the placement pattern at IITs as PSUs offer jobs to many students in one go

tion has gone up from four last year to 13 this year. Some of the big names include Indian Oil, HPCL, BPCL, and BEL.

Bigger participation from the sector will change the placement pattern as the PSUs offer jobs to many students in one go. "Last year, Coal India recruited around 31 students,"

said Debashis Deb, placement chairperson at IIT-Kharagpur. Besides, a PSU job is more secure with proper pay scales and attractive post-retirement benefits, Deb pointed out.

"PSUs also consider the student community as a whole and even weaker ones find plum positions," said another teacher.

Kaustubha Mohanty, placement chairperson of IIT Guwahati and convener of the All-IIT Placement Committee, said the number of PSUs at the Guwahati campus has gone up from three last year to seven. "The Mad-

ras high court dismissing a plea against direct recruitment by PSUs could be a reason," he said.

At IIT Madras, eight PSUs have confirmed participation. "The new ones this year are Coal India, ONGC, HPCL, Midhani (Miniratna) and BEL," said Manu Santhanam, chairman of placements at IIT-Madras. "After implementation of the seventh pay commission, PSUs are offering salaries at par with the private sector. Add to this job stability and clearly PSUs emerge as more lucrative employers," Santhanam said.

Hindustan ND 27.11.2016 P-5

● इस बार से कैट पर्सेंटाइल का महत्व घट जाएगा ● 10वीं और 12वीं में बेहतर अंक मददगार होंगे

आईआईएम दाखिले में नया फॉर्मूला

बदलाव

नई दिल्ली | विवेक तिवारी

कैट परीक्षा में बहुत अच्छा पर्सेंटाइल नहीं आने पर भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में आए अंक तथा अन्य पैमानों पर उम्दा प्रदर्शन आपको मनपसंद आईआईएम में दाखिला दिला सकता है। आईआईएम की वर्ष 2017-19 बैच के लिए घोषित की गई नई दाखिला नीति में लगभग सभी आईआईएम ने कैट के तहत मिले अंकों के महत्व को कम कर अन्य पैमानों पर स्कोर करने वाले छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कही है।

आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम लखनऊ सहित बाकी आईआईएम ने अपनी नई दाखिला नीति के तहत कैट 2016 में आए स्कोर को 40 से 70 फीसदी तक कम महत्व देने की बात कही है।

वहीं, आईआईएम अहमदाबाद में आप कैट में सेक्शनल पर्सेंटाइल 70 व कुल पर्सेंटाइल 80 होने पर भी दाखिला पा सकते हैं। उधर, आईआईएम कोलकाता ने सेक्शनल पर्सेंटाइल की न्यूनतम सीमा 80 व कुल पर्सेंटाइल की न्यूनतम सीमा 90 प्रतिशत रखी है। कैट में ये स्कोर आने पर आप प्राथमिक तौर



● फाइल फोटो

पर दाखिले के लिए योग्य मान जाएंगे। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट तथा स्नातक में अच्छे अंक हैं तो आपकी दाखिले की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी।

गैर तकनीकी विषयों के छात्रों को प्राथमिकता: आईआईएम की नई दाखिला नीति में इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आने वाले छात्रों को कम तरजीह मिल सकती है। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स व अन्य गैर तकनीकी विषयों के छात्रों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।

अनुभव वालों को वरीयता

दो से तीन वर्षों के काम का अनुभव आपको दाखिले की दौड़ में मदद करेगा। हालांकि आपका काम का अनुभव सुपरवाइजर के तौर पर होना चाहिए। वहीं यदि आपने किसी एनजीओ, शिक्षा या समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है जो आपकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है तो आपकी कार्यअनुभव की श्रेणी में प्राथमिकता मिलेगी। इस श्रेणी में अधिकतम 5 से 10 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा।

किस आईआईएम में क्या बदलाव किए गए

अहमदाबाद

आईआईएम अहमदाबाद ने सेक्शनल पर्सेंटाइल को 70 व कुल पर्सेंटाइल न्यूनतम 80 फीसदी करने की घोषणा की है। वहीं, गैर इंजीनियरिंग छात्रों को महत्व दिया जाएगा।

बेंगलुरु

आईआईएम बेंगलुरु ने कैट 2016 के अंकों को 40% वेटेज देने की बात कही है। गत वर्ष यहां कैट वेटेज 30.3% थी। बाकी के 60 फीसदी अंक छात्रों को उनके कक्षा 10, 12 व स्नातक के अंकों, अनुभव, शैक्षणिक विविधता व लेगिक विविधता के आधार पर दिए जाएंगे। यहां छात्रों को दो फीसदी तक महत्व दिया जाएगा।

लखनऊ

आईआईएम लखनऊ ने कैट 2016 के अंकों को मात्र 60 फीसदी तक महत्व देने की बात कही है। पिछले वर्ष यहां कैट पर्सेंटाइल को 78 फीसदी तक का महत्व दिया गया था।

कोलकाता

आईआईएम कोलकाता ने कैट 2016 के कैट स्कोर का महत्व काफी कम करने की घोषणा की है। यहां कैट 2016 के वेटेज को 56 फीसदी कर दिया गया है पिछले वर्ष यह 67 फीसदी था। यहां कक्षा 12 तक के अंकों को 40 फीसदी तक वेटेज दी जाएगी। यदि छात्र के कक्षा 12 में अच्छे अंक हैं तो दाखिले की संभावना बढ़ जाएगी।

वर्षवार कैट वेटेज का अंतर

आईआईएम	2016-18	2017-19
बेंगलुरु	30.3	40
कोलकाता	67	56
रायपुर	100	100
उदुपपुर	100	100
बोधगया	100	100

नोट: कैट के वेटेज का आंकड़ा प्रतिशत में है।

अधिकांश आईआईएम कैट के अंकों को प्राथमिकता

देकर दाखिला देते हैं। जिनमें कुछ बदलाव किए हैं, ऐसा संभव है कि वह अगले वर्ष फिर से बदलाव करें। छात्र भ्रमित न होकर कैट पर ही ध्यान दें। - अंकुश जैन, वीक नॉलेज एक्सपर्ट, टाइम कोरिंग

November 26

Hindustan Times ND 26.11.2016 P-10

IITs, central varsities asked to go cashless

Neelam Pandey

neelam.pandey@hindustantimes.com

NEW DELHI: The HRD ministry has asked all the higher educational institutions including IITs, NITs and central universities to go cashless in all their transactions. This comes as part of the Human Resource Development (HRD) ministry's push for switching to a digital platform, officials said.

A few IITs had approached the ministry post demonetisation seeking relaxation from the cash withdrawal limit of ₹24,000 per week claiming they have to spend substantial amount on maintenance of their huge campuses on a daily basis.

"Keeping in mind its policy towards promoting cashless transactions, the government has asked all the higher educa-

tional institutions not to make payments in cash," said a senior HRD official.

Institutions have been told that digital payment modes such as online transfer and payment through mobile wallet should be adopted, irrespective of who the payee is.

All institution heads have been asked to call a meeting to discuss the modalities and issue directions to the account sections of their institute. "This will take care of the issue arising out of the shortage of cash. It will also ensure digital platform compliance," said a senior official.

A number of IITs had requested the ministry to take up the issue of withdrawal restrictions with the finance ministry. Most of the IITs spend at least ₹1 lakh on maintenance every day.

Times Of India ND 26.11.2016 P-21

IIT-M to help CERN unravel mysteries of the universe

U.Tejonmayam
@timesgroup.com

Chennai: In 2025, when scientists at CERN, the European Organisation for Nuclear Research, start looking for signs of a new charged particle from the massive 14,000 tonne CMS (Compact Muon Solenoid) detector installed in France, a silicon tracker detector built by Indian Institute of Technology-Madras (IIT-M) will be among the key tools. Data from the main detector 100m below ground may help scientists understand the evolution of the Universe better.

The silicon detector made by IIT-M will replace the existing detector when it dies out by 2025. IITM professor Prafulla Kumar Behera, who is the co-convenor, B-physics subgroup in CMS, said that the institute will be building part of the silicon detector in collaboration with other Indian institutes. The silicon detector will be one of the four sub-detectors in the main CMS detector.

INSTITUTE TO BUILD DETECTOR

➤ **CMS (Compact Muon Solenoid) is a particle physics experiment** that will help scientists understand how the universe evolved and more

➤ **Silicon tracker detector, which is built by IIT-M,** is one of the four sub-detectors to be installed in the CMS detector in France as part of CMS experiment at CERN, the European Organisation for Nuclear Research



➤ **The silicon detector will help scientists track new particles** along with other particles

➤ **It will be installed** in the main CMS detector by 2025

➤ **India will also manufacture 2,000 sensors** for the detector

“IITM will fabricate high-precision mechanics made of aluminum carbon fibre and carbon fibre. They are lightweight materials that support structure for the sensors in the detector,” he said. This is not the first time, a detector for CERN is built in India. A part of a detector for the Large Hadron Collider, which helped scientists discover Higgs Boson in 2012, was built in India.

A CMS detector is designed to see a wide range of particles produced during high-energy collision of protons. When this hap-

pens, scientists will essentially be recreating a very small model of the state of the universe when it was in the first trillionth of a second after the Big Bang.

The silicon detector, which will be installed near the collision point, will give the position of the particle when it travelled through the detector. The magnetic field in the CMS detector will help find the momentum of the particle. For physicists this data is key as it will help draw a picture of events at the heart of the collision.

Hindu ND 26.11.2016 P-20

IIT team tracks brown carbon's effect on atmospheric warming

High levels of the aerosol found in Kanpur due to biomass burning

R. PRASAD

CHENNAI: The effect of biomass burning in increasing atmospheric aerosols and in turn atmospheric warming through light absorption has been highlighted in a study by a team of researchers from the Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur.

While the role of black carbon produced by biomass burning in increasing atmospheric warming has already been well established, this study highlights the lesser-known role of brown carbon.

Compared with earlier studies carried out in the U.S, absorption of light of 365 nanometre wavelength was found to be five times higher in Kanpur, which has a high biomass burning area. Also, brown carbon accounts for about 30 per cent of light absorption in Kanpur. The results were published on November 24 in the journal *Scientific Reports*.

"What is seen in Kanpur



(From left) P.M. Shamjad, S.N. Tripathi and Navaneeth Thamban of IIT Kanpur. — PHOTO: SPECIAL ARRANGEMENT

can be generalised for the entire Indo-Gangetic Plain because the sources of aerosol remain the same throughout the region," says P.M. Shamjad from the Department of Civil Engineering, IIT Kanpur, and the first author of the paper.

"Based on 50 days of measurement in the winter of 2014-2015 we were able to clearly apportion the amount of light absorption by different carbonaceous aerosols. Though brown car-

bon is 10 times more than black carbon in terms of mass, the absorption capacity of black carbon is 50 times more than brown carbon," says Prof. S.N. Tripathi from the Department of Civil Engineering, IIT Kanpur, and the corresponding author of the paper.

As a result, up to about 70 per cent of light absorption during 24 hours is by black carbon. Brown carbon (when present independently) has nearly 15 per cent

potential to warm the atmosphere by absorbing light.

Additionally, depending on the spectrum of light, the light absorption capacity of brown carbon is 15-30 per cent when present as a coating (shell) over a black carbon core. "This is because the brown carbon coating behaves like a lens and focuses light towards the black carbon core," says Mr. Shamjad.

The lensing (concentration of light on the core) is dependent on three parameters — ratio of the diameter of the shell to the diameter of the core, wavelength of light and the scattering or absorbing property of the coating. "When you have an absorbing coating less light reaches the core. But when the coating is non-absorbent, light gets scattered and more light reaches the core. This leads to more overall light absorption and, in turn, more atmospheric warming," says Prof. Tripathi.

Amar Ujala ND 26.11.2016 P-6

जेईई मेंस के लिए आधार कार्ड बनवाएगा सीबीएसई

आधार कार्ड नामांकन के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए गए

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जेईई मेंस (ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) के आवेदनकर्ताओं के लिए आधार कार्ड भी बनवाएगा। बोर्ड ने इसके लिए जिन शहरों में परीक्षा होनी है, वहां आधार कार्ड नामांकन के लिए विशेष सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर आधार नामांकन के लिए छात्रों से कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा। इससे छात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशानी नहीं उठानी होगी।

मालूम हो कि सीबीएसई ने जेईई मेंस-2017 के आवेदन के लिए आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य किया है। दरअसल, सीबीएसई का मानना है कि आधार कार्ड होने से परीक्षा सेंटर पर आवेदक की पहचान सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक हैं जो कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण आवेदन करने से वंचित हो सकते



हैं। लिहाजा बोर्ड ने ऐसे छात्रों की सहूलियत के लिए यह कदम उठाया है। बोर्ड ने साफ किया है कि आवेदक बोर्ड के सुविधा केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने जेईई मेंस की वेबसाइट www.jeemain.nic.in पर सुविधा केंद्रों की सूची उपलब्ध करा दी है। जिन छात्रों ने आधार कार्ड के लिए नामांकन कर दिया है लेकिन अब तक उन्हें आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे उम्मीदवारों को जेईई मेंस के ऑनलाइन आवेदन के

जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय के आवेदकों को पासपोर्ट नंबर देना होगा

समय आधार नामांकन स्लिप में दिए गए 28 अंकों के आधार नामांकन नंबर को लिखना होगा। बोर्ड के अनुसार यदि किसी सुविधा केंद्र पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध न मिलने पर आवेदकों को आधार नामांकन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

इसके बाद सुविधा केंद्र की ओर से एक पंजीकरण नंबर जारी किया जाएगा। जिस आवेदक जेईई मेंस के ऑनलाइन आवेदन के समय पर सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर, असम व मेघालय के 12वीं पास छात्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन राज्यों के छात्रों को पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक एकाउंट नंबर या अन्य सरकारी पहचान पत्र नंबर देना होगा। आवेदक सरकारी आधार नामांकन सेंटर पर जाकर भी नामांकन कर सकते हैं।

Veer Arjun ND 26.11.2016 P-11

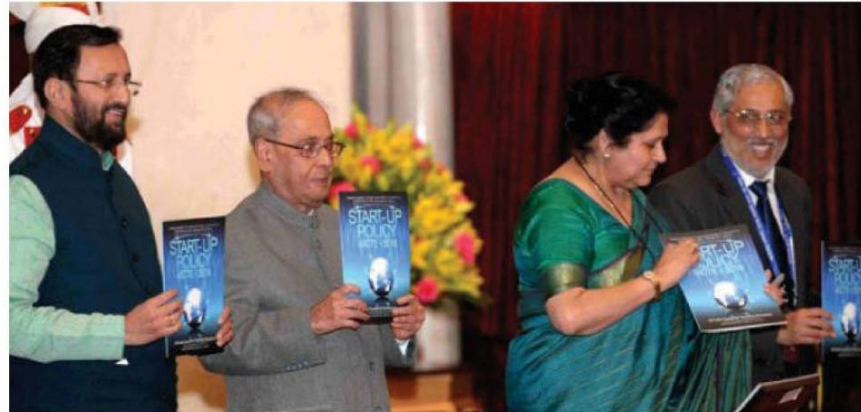
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय स्टूडेंट स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय स्टूडेंट स्टार्टअप नीति (एनएसएसपी) का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, "स्टार्टअप इकोसिस्टम की वैश्विक रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है और एआईसीटीई की स्टार्टअप नीति को मदद से हमारा उद्देश्य विश्व में पहले नंबर की स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने का होना चाहिए।"

इस उद्घाटन समारोह में 126 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं गणमान्य व्यक्ति, आईआईटी एवं एनआईटी के निदेशक भी मौजूद थे।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एआईसीटीई ने छात्रों को नौकरी उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने नीति के कार्यान्वयन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुधे ने कहा, 'स्टूडेंट स्टार्टअप नीति को उद्यमशीलता को छात्रों के लिए एक मुख्य धारा का कैरियर विकल्प बनाकर भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप पावरहाउस बनाने की प्रक्रिया



में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के साथ संबद्ध किया गया है।"

एनएसएसपी डॉ. सहस्रबुधे की एक नयी पहल है जिन्होंने इस स्टूडेंट स्टार्टअप कार्यक्रम के दो कारकों की कल्पना की 1) नीति बनाना और 2) नीति को कार्यान्वित करना। उन्होंने दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया और उन्हें काम सौंपा गया। नीति डिजाइनिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. अक्षय अग्रवाल हैं, जो गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति (जीटीयू) हैं और जिन्होंने गुजरात में उद्यमिता विकास का एक अनूठा मॉडल बनाया है और नीति कार्यान्वयन समिति

के अध्यक्ष संजय इनामदार हैं, जो पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं।

नीति समिति में संजय विजयकुमार और हीरानमय मोहंता जैसे अग्रणी स्टूडेंट स्टार्टअप विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने निरंतर प्रयासों और अभिनव छात्र अनुकूल दृष्टिकोण के साथ स्टार्टअप पर केरल और गुजरात राज्यों का नेतृत्व किया है। एआईसीटीई 10000० संस्थानों और 80 लाख ८ छात्रों को कवर करता है। नीति का उद्देश्य 2025 तक देश में दस लाख

से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा कर अगले 10 वर्षों में 1,00,000 स्टूडेंट स्टार्टअप सृजित करना है। इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप को वित्तीय मदद पहुंचाने तथा इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एआईसीटीई नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में काम करेगी। डॉ. प्रणव मुखर्जी इस नीति तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।